

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग

देहरादून : दिनांक 01 अक्टूबर 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में गंगा कार्ययोजना के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 167/उन्तीस(2)/09-2(63पे0)/09टीसी दिनांक 02 मार्च 2010 द्वारा गंगा कार्य योजना परिसम्पत्तियों के रखरखाव के अन्तर्गत हरिद्वार/ऋषिकेश नगरों में प्रदूषण नियंत्रण कार्य हेतु टीएसी वित्त द्वारा संस्तुत रु० 1261.14 लाख के सापेक्ष रु० 800.00 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही इतनी ही धनराशि अवमुक्त की गयी है। तद्विषयक आपके पत्र संख्या 627/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/31 दिनांक 23.03.10 एवं पत्र संख्या 2119/न०यो०अनु०/NGRB/111 दिनांक 13.09.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में हरिद्वार/ऋषिकेश नगरों में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्य के रखरखाव हेतु अवशेष ₹ 373.24 लाख (₹ तीन करोड़ तिहत्तर लाख चौबीस हजार मात्र) धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित इतनी ही धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय इस हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

2- चूंकि यह कार्य संचालन एवं रखरखाव से सम्बन्धित है, अतः इस कार्य हेतु सैन्टेज चार्ज अनुमन्य नहीं होगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर्स की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त स्वीकृति से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा मासिक व त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करायेगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को चालू वित्तीय वर्ष की 31.12.2010 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5- गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव का राज्य सरकार की वचनवद्धता की सीमा तक धनराशि व्यय की जा सकेगी और इसके अभिलेखों का रखरखाव योजनावार अलग-अलग किया जायेगा। आपरेटिंग तथा अतिरिक्त स्टाफ का खर्च विगत वर्ष की योजना से इस वर्ष अनुमोदित लागत की सीमा में ही सुनिश्चित किया जायेगा। अन्य मदों में भी अनुमोदित लागत से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। यदि किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व शासन का नहीं होगा वरन अपने संसाधनों से किया जायेगा।

- 6- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। साथ ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 7- उक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
- 8- दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करा लिया जाय।
- 9- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में व्यय अनुमन्य न होगा।
- 10- कार्य स्वीकृत राशि तक ही सीमित रखे। अधिक्य किसी भी दशा में न किया जाय। अधिक्य के लिए निर्माण इकाई स्वयं उत्तरदाई होगा।
- 11- रखरखाव तथा मशीनों पर व्यय नियमानुसार एवं स्वीकृत मानको के आधार पर ही किया जाय।
- 12- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों से कार्य स्थल का भलीभाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- 13- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- 14- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य करना सुनिश्चित करें।
- 15- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV- 219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 16- उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 167/उन्तीस (2)/09-2(63पे0)/ 09 टीसी दिनांक 02 मार्च 2010 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
- 17- सम्बन्धित परिसम्पत्तियों के रखरखाव व संचालन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र इस हेतु प्राधिकृत संस्था को हस्तान्तरण किया जाय एवं ऐसा होने तक निगम द्वारा यूजर चार्ज वसूल करना सुनिश्चित किया जाय।
- 18- उक्त व्यय वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मल निकासी एवं सफाई- आयोजनागत -106-वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण-03-गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल निगम को अनुदान (फेज- I एवं II)- 00-20-सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
- 19- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 296/XXVII(2) /2010, दिनांक 27 सितम्बर 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

पू0सं0-126(1)/उत्तीस(2)/09-2(63पे0)/09 टीसी तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार ।
4. कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तराखण्ड पेयल निगम हरिद्वार ।
6. वित्त अनुभाग-2/नियोजन/राज्य योजना आयोग/बजट सेल ।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
10. गार्ड फाईल ।

महोदय

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव